[2014] 14 एस सी आर 1468

पूजा राविंदर देवीदासानी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्यायें 2604-2610/ 2014)

17 दिसंबर, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और एन. वी. रमना, जे.जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 धारा 141 - प्रतिवर्ती दायित्व - का अनुमान: धारा 141 के तहत दायित्व का अनुमान किसी व्यक्ति पर तभी लगाया जा सकता है जब ऐसा व्यक्ति कंपनी के मामलों के शीर्ष पर था और सक्रिय रूप से इसके दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखभाल कर रहा था। भौतिक समय - ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट अभिकथन होना चाहिए जिसमें यह दर्शाया जाए कि वह व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी था

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482- परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू - धारित को रद्द करना: आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में सबूतों की जांच किए बिना आपराधिक कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए और

यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या अपराध वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया किया गया था, अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है - अपीलकर्ता को कंपनी के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें उसकी भूमिका है कंपनी के रोजमर्रा के मामलों की व्याख्या नहीं की गई - परक्राम्य अधिनियम, 1881-धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. किसी आपराधिक मामले में आरोपी को तलब करना गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को यूं ही क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करनी होगी और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और यहां तक कि आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए या अन्यथा उत्तर जानने के लिए शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से खुद भी सवाल पूछ सकते हैं और फिर जांच करें कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या किसी भी आरोपी द्वारा किया गया है। [पैरा 22][1483-एफ-एच; 11-84-ए-बी]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य ( 1998 ) 5 एससीसी 343: 1998 ( 3 ) एस. सी. आर. 104- पर निर्भर।

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के तहत किसी व्यक्ति पर प्रत्यावर्ती दायित्व तय करना, उस समय वह व्यक्ति कंपनी के मामलों के शीर्ष पर रहा होगा, जो सक्रिय रूप से कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल करता है। कंपनी और विशेष रूप से अपने व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, उसे अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा. निदेशक के खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए, जिससे पता चले कि निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कैसे और किस तरह से जिम्मेदार था। [पैरा 17 और 20][1481-डी-एफ; 1483-ए]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाम हरमीत सिंह पेंटल और अन्य 2010 (3) एससीसी 330: 2010 (2) एससीआर 805; गिरधारी लाल गुप्ता बनाम डी. एच. मेहता और अन्य (1971) 3 एससीसी 189: 1971 (3) एस. सी. आर. 748; कर्नाटक राज्य बनाम प्रताप चंद और अन्य (1981) 2 एससीसी 335 : 1981 (3) एस सी आर 200; सबिथा राममूर्ति और अन्य बनाम आर. बी. एस. चन्नबसवराध्य (2006) 10 एससीसी 581: 2006 (6) पूरक एससीआर 126-पर निर्भर।

3. धारा 141 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के बारे में केवल तभी सूचित किया जा सकता है जब आवश्यक बयान, जो शिकायत याचिका में दिए जाने आवश्यक हैं, दिए गए हैं ताकि आरोपी को कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। उचित साक्ष्य द्वारा समर्थित तथ्य के स्पष्ट बयान के बिना धारा के शब्दों को शब्दशः पुनः प्रस्तुत करना, ताकि आरोपी को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 141 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का आधार है । [ पैरा 21] [1483-डी-ई]

4. अपीलकर्ता द्वारा निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का तथ्य स्थापित हो गया है। यदि एक ही तारीख को कंपनी में दो व्यक्तियों को निदेशक-संचालन के रूप में शामिल किया गया था, तो अपीलकर्ता निदेशक नहीं रह गया था, प्रतिवादी संख्या 2 निदेशकों के परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानता था। प्रतिवादी नंबर 2 एक तरफ फॉर्म 32 की वास्तविकता के बारे में संदेह उठाता है, एक सार्वजनिक दस्तावेज, जिसके माध्यम से डिफ़ॉल्ट कंपनी ने कंपनियों के रजिस्ट्रार को निदेशकों के परिवर्तन के बारे में सूचित किया था और दूसरी तरफ उसने दो नए को सूचीबद्ध किया है। निदेशक-संचालन को आरोपी के रूप में नियुक्त किया गया, जिनके नाम कंपनी रजिस्ट्रार को उसी फॉर्म 32 द्वारा सूचित किए गए थे। [पैरा 24,25 और 26] [1485-डी; 1486-ए-सी, ई]

5. पूरी शिकायत में न तो कंपनी के मामलों में अपीलार्थी की भूमिका के बारे में बताया गया था और न ही यह समझाया गया था कि अपीलार्थी किस तरीके से कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा व्यापार वित्त सुविधा का विस्तार किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा निदेशक मंडल से इस्तीफा देने के बाद डिफ़ॉल्ट कंपनी को। [ पैरा 28] [ 1487 - बी-डी]

6. इसलिए अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे शुरुआत में ही रोकना होगा। [पैरा 28] [1487-डी]

7. यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत उत्तरदायी है क्योंकि चेक अपीलकर्ता-अभियुक्त के गारंटी पत्र के आधार पर जारी किए गए थे। अपीलकर्ता द्वारा जारी गारंटी पत्र नागरिक दायित्व के लिए रास्ता देता है। उन पक्षों के बीच के विवाद को निपटाने के लिए जो एक नागरिक विवाद की प्रकृति के हैं, पार्टियों को आपराधिक कानून लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अदालतें इसके लिए केवल दर्शक नहीं बन सकती हैं। वरिष्ठ न्यायालयों को न्याय प्रशासन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। [पैरा 29 और 30][1487-ई-एच;1488-ए]

गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनु मेहता और अन्य 2015 (1) एस. सी. सी. 104,-पर भरोसा किया।

चांद धवन बनाम जवाहर लाल (1992) 3 एस. सी. सी. 317:1992 (2) एस. सी. आर. 837; मालवा कपास और कताई मिल्स लिमिटेड बनाम विरसा सिंह सिद्धू (2008) 17 एससीसी 147 : 2008 (12 ) एस. सी. आर. 68-संदर्भित।

संदर्भः

| | |
|---|---|
| 1992 (2) एससीआर 837 संदर्भित किया गया है | पैरा 12 |
| 2008(12) एससीआर 68 संदर्भित किया गया है | पैरा 12 |
| 2015(1) एससीसी 104 उस पर भरोसा करें | पैरा 14 |
| 2010(2) एससीआर 805 उस पर भरोसा करें | पैरा 17 |
| 1971 (3) एससीआर 748 उस पर भरोसा करें | पैरा 18 |
| 1981 (3) एससीआर 200 उस पर भरोसा किया | पैरा 19 |
| 2006 (6) पूरक एससीआर 126 पर भरोसा किया गया | पैरा 21 |
| 1998 (3) एससीआर 104 उस पर भरोसा करें | पैरा 22 |

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 2604-2610/ 2014

2010 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 614-620 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.10.2010 से।

अखिल सिब्बल, श्रीमती वनिता भार्गव, अजय भार्गव, नितिन मिश्रा, प्रदीप छिंदरा, निखिल चावला (मेसर्स खेतान और कं.) अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

गौरव पचनंदा, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीजू मट्टम, तबरेज एम., सुश्री श्रुति गुप्ता, सुश्री इंदु शर्मा, ए. पी. मयी, नितिन लोनकर, ए.सेल्विन राजा, सुश्री आशा गोपालन नायर, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति एन. वी. रमना

1. अनुमति दे दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका संख्या 614-620 ऑफ 2010 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 6 अक्टूबर, 2010 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद इसे "एनआई अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर की गई शिकायतों को रद्द करने की मांग की गई है।

3, इन अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 एक वित्त कंपनी ने अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ एन आई अधिनियम के तहत सात शिकायतें दर्ज कीं, जैसे (1) शिकायत सख्या 3370/एसएस/2008 जिसमे 1,64,69,801-14 रुपये का दावा करते हुए (2) शिकायत संख्या 3641/एसएस/2008 जिसमें 1,06,55,289-91 रुपये का दावा करते हुए (3) शिकायत संख्या 3368/एसएस/2008 जिसमें 1,41,95,806-40 रुपये का दावा करते हुए (4) 3640 / एस एस/2008 जिसमें 85,21,294 रुपये का दावा कर रहा है। (5) 3369/ एसएस/2008 जिसमें रु. 1,88,12,292 का दावा - (6) 3642 / एसएस/2008 जिसमें 1,69,95,353-50 रुपये का दावा कर रहा है और (7) शिकायत संख्या 4086/एसएस/2009 के दावे के लिए रु. 8,08,973-25

सभी शिकायतों में आरोप यह था कि प्रतिवादी नंबर 2 कंपनी ने मेसर्स को व्यापार वित्त सुविधा प्रदान की थी। एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता निदेशक था और आंशिक भुगतान के प्रति अपनी देनदारी के निर्वहन के लिए मेसर्स एलीटइंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 8,64,58,810-16 रुपये के कई चेक (संख्या में 119) जारी किए गए थे। बैंकर की टिप्पणी "अपर्याप्त धनराशि" से अपमानित होना पड़ा। शिकायतकर्ता के अनुसार, भौतिक समय पर आरोपी (अपीलकर्ता) मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का प्रभारी और मामलों का मुखिया था। लिमिटेड और इसलिए वह कंपनी के चूक के लिए

परोक्ष रूप से उत्तरदायी है क्योंकि वह इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 12 वीं अदालत, बांद्रा, मुंबई ने शिकायतों पर संज्ञान लिया और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी (अपीलकर्ता) के खिलाफ प्रक्रिया जारी की।

4. पीड़ित अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिकाएं दायर कीं। चाह रहा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना। उच्च न्यायालय ने शुरुआत में 28 जुलाई, 2010 के एक अंतरिम आदेश द्वारा अपीलकर्ता के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अंततः आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। बर्खास्तगी के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष ये अपील दायर की है।

5. विद्वान वकील द्वारा दिया गया मुख्य तर्क अपीलकर्ता के लिए यह है कि अपीलकर्ता केवल एक गृहिणी है जिसे मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन में विशेष रूप से चेक जारी करने में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। . तथ्य की बात यह है कि अपीलकर्ता ने चेक जारी होने से बहुत पहले निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके इस्तीफे को 17 दिसंबर, 2005 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल

द्वारा अनुमोदित भी किया गया था: मेसर्स एलीट के निदेशक पद से अपीलकर्ता का इस्तीफा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी सूचित कर दिया गया है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 159 अनुसूची V, भाग II के तहत फॉर्म नंबर 208 द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार, जब 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा उसी तारीख को निष्पादित गारंटी पत्र के अनुसार व्यापार सुविधा को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा 19 जनवरी, 2005 को मंजूरी दी गई थी। कंपनी के निदेशक के रूप में अपीलकर्ता के इस्तीफे की प्रभावी तिथि 17 दिसंबर, 2005 थी। निदेशक मंडल द्वारा उसके इस्तीफे की मंजूरी के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने कंपनी की गतिविधियों में कोई भूमिका निभाना बंद कर दिया। कंपनी द्वारा चेक वर्ष 2008 में जारी किए गए थे, यानी निदेशक के रूप में अपीलकर्ता के इस्तीफे के लगभग ढाई साल बाद। यह तथ्य स्वयं इस बात पर जोर देता है कि जब चेक जारी किए गए थे तब अपीलकर्ता कंपनी के मामलों में शामिल नहीं था और उसके पास कोई नहीं था। कंपनी के व्यवसाय के संचालन में या चेक जारी करने में भूमिका।

6. निदेशक के रूप में अपीलार्थी के इस्तीफे के बाद, प्रपत्र 32 कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, धारा 303 (2) के अनुसार, मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। लिमिटेड ने 20 दिसंबर, 2005 को कंपनी पंजीयक के साथ निदेशकों के बीच नियुक्तियाँ और परिवर्तन का संकेत दिया। उक्त फॉर्म 32 में, दो निदेशकों के नाम जिन्हें नव नियुक्त किया गया था"निदेशक-संचालन के रूप में नियुक्त" टिप्पणियों के साथ दिखाया गया था और अपीलकर्ता के नाम के सामने "निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया" टिप्पणियों को दिखाया गया था। इस प्रपत्र 32 को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने नव नियुक्त निदेशकों को इस प्रकार रखा: अभियुक्त नं. 4 & 5 शिकायतों में। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि अपीलार्थी अब मैसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट का हिस्सा नहीं था। लिमिटेड ने अभी तक अपीलार्थी पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की है जिस पर प्रत्यावर्ती दायित्व को तय किया गया है

7. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यावर्ती दायित्व को मजबूत करने के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता को यह साबित करना चाहिए कि अपीलार्थी कंपनी के व्यवसाय के संचालन में कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार था। शिकायतकर्ता को धारा 141 (1) के प्रावधान के आलोक में यह भी बताना होगा कि अपीलकर्ता किस क्षमता में प्रासंगिक समय पर डिफ़ॉल्ट कंपनी के

दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी था, खासकर जब चेक जारी किए गए थे।प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) ने इन्हें पूरा नहीं किया अधिनियम में पूर्वापेक्षाओं पर विचार किया गया है, लेकिन अपीलकर्ता पर केवल इस तथ्य के कारण परोक्ष दायित्व थोपने की मांग की गई है कि अपीलकर्ता ने मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड बैठक में भाग लिया था। लिमिटेड की बैठक 14 अगस्त, 2004 को हुई। उस बैठक में निदेशक मंडल ने प्रतिवादी संख्या 2 से व्यापार वित्त सुविधा के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए एक अन्य निदेशक को अधिकृत किया। 14 अगस्त, 2004 को बोर्ड की बैठक में अपीलकर्ता की उपस्थिति मात्र नहीं मानी जाएगी। एन.आई. की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध कार्यवाही करना। किसी कंपनी के निदेशक को शिकायत में आरोपी के रूप में पेश करना और कोई विशिष्ट भूमिका बताए बिना यह कहना कि व्यवसाय के संचालन के लिए निदेशक जिम्मेदार है, कंपनी के निदेशक के खिलाफ परोक्ष दायित्व का मामला नहीं बनेगा। एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत। इसी तरह, केवल यह कहना कि अपीलकर्ता कंपनी के मामलों का प्रभारी था, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, शिकायतकर्ता को भूमिका स्पष्ट करनी होगी। अपराध के लिए विशेष रूप से अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाम हरमीत सिंह पेंटल और अन्य (2010) 3 एससीसी 330 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस

न्यायालय द्वारा कई मामलों में कानून अच्छी तरह से तय किया गया है, शिकायतकर्ता को विशेष रूप से यह दिखाना चाहिए कि कैसे और क्या जिस तरह से आरोपी जिम्मेदार है।

8. प्रतिवादी संख्या 2 को इसकी जानकारी होने के बावजूद कंपनी के निदेशक के रूप में अपीलकर्ता का इस्तीफा और प्रश्न में चेक जारी करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी हाथ मरोड़ने के उपाय के रूप में, शिकायतकर्ता ने शिकायत में अपीलकर्ता को डिफॉल्टर के रूप में दर्ज किया और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। निदेशकों के परिवर्तन के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 ने अनावश्यक रूप से अपीलकर्ता का नाम मुकदमे में आकस्मिक और संवेदनहीन तरीके से घसीटा और कंपनी के मौजूदा निदेशकों के साथ उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की, जो कानून के तहत अस्थिर है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उचित विवेक के बिना प्रक्रिया जारी की और उच्च न्यायालय ने भी एनआई अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधान की व्याख्या करने में गलती की और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिकाओं को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

9 अपने इस तर्क के समर्थन में कि अपीलकर्ता अब कंपनी का निदेशक नहीं है और प्रासंगिक समय पर इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार है, विद्वान वकील ने निम्नलिखित पर भरोसा किया

(i) दिनांक 17 दिसंबर, 2005 की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का एजेंडा आइटम 4 जो निम्नानुसार है

"4. निदेशक का इस्तीफा

अध्यक्ष ने बोर्ड के सदस्यों के समक्ष सुश्री पूजा देवीदासानी से कंपनी के निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा देने का पत्र रखा। बोर्ड के सदस्यों ने इसे नोट किया और फिर उन्होंने सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया:

निर्णय लिया गया कि सुश्री पूजा देवीदासानी द्वारा दिया गया इस्तीफा इस बोर्ड बैठक के समापन से स्वीकार कर लिया जाएगा।"

(ii) फॉर्म 32 कंपनी रजिस्ट्रार को जमा किया गया कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसरण में, जिसमें अपीलकर्ता के नाम के सामने इसे "निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया गया" के रूप में दिखाया गया था। जबकि श्री हितेश हरिया और श्री पराग तेजानी के नाम के सामने, "निदेशक संचालन के रूप में नियुक्त" शब्द दिखाया गया था। "नियुक्ति या परिवर्तन की तिथि" कॉलम के सामने उपरोक्त सभी तारीखें अंकित करें 17 दिसंबर 2005 को तीन व्यक्तियों को दर्शाया गया था।इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी नंबर 2 ने नए जोड़े गए निदेशकों को डिफॉल्टर के रूप में सूचीबद्ध किया, लेकिन उस अपीलकर्ता को नहीं छोड़ा जिसने निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है, जो कि फॉर्म 32 में निर्दिष्ट है।

(iii) 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दायर वार्षिक विवरणी जिसमें यह भी दिखाया गया है कि अपीलार्थी अब कंपनी के निदेशक नहीं थे। वार्षिक विवरणी के कॉलम IV में अपीलकर्ता के नाम के सामने स्पष्ट रूप से "समाप्ति की तिथि 17-12-2005" का उल्लेख किया गया था।.

iv) डिफॉल्ट कंपनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 5 फरवरी, 2009 को जारी एक पत्र। उक्त पत्र में कुछ विवरण/जानकारी अग्रेषित करते समय निदेशकों की एक सूची भी भेजी गई थी। उक्त सूची में अपीलकर्ता का नाम नहीं था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 2 को पूरी तरह से पता था कि अपीलार्थी को कंपनी का निदेशक नहीं रह गया था (ए) चेक जारी करने से पहले (बी) चेक के अनादरण से पहले (सी) कानूनी नोटिस जारी करने की तारीख से पहले (डी) कानूनी आदेश जारी होने के बाद 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले नोटिस जिसके बाद आपराधिक शिकायतें दर्ज करने के लिए कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ और (ई) आपराधिक शिकायतें दर्ज करने से पहले।

10. विद्वान वकील ने अंततः प्रस्तुत किया कि आरोप शिकायत में उल्लिखित अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं है।और उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट त्रुटि की एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की उचित परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने में जिसके कारण न्याय का उपहास हुआ। इसलिए उन्होंने

आक्षेपित निर्णय को रद्द करने और अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आग्रह किया।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की रिट याचिकाओं को खारिज करके उच्च न्यायालय ने न तो कोई अवैधता की है और न ही एन.आई. अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है। अपीलकर्ता का इस्तीफा अपने आप में एक विवादित तथ्य है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा फॉर्म 32 की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी और केवल वार्षिक रिटर्न की प्रमाणित प्रति ही इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 79 के तहत, एक न्यायालय कर सकता है

किसी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता तभी मानें जब प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गई हो, भले ही अपीलकर्ता द्वारा फॉर्म 32 की प्रमाणित प्रति यह तर्क देने के लिए प्रस्तुत की गई हो कि चेक जारी करने के समय उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जब शिकायतकर्ता द्वारा ऐसे फॉर्म 32 पर विवाद किया जाता है, तो यह माना जाएगा अपीलकर्ता का यह परम कर्तव्य है कि वह मुकदमे में सबूत पेश करके ऐसे फॉर्म 32 को साबित करे। एन आई अधिनियम की धारा 141 के साथ पढ़ी गई धारा 138 के तहत शिकायत को रद्द करने के लिए केवल फॉर्म 32 की एक प्रति प्रदान करना, इसकी सामग्री को साबित किए बिना, पर्याप्त नहीं होगा।

12 अपने तर्क के समर्थन में कि जब फॉर्म 32 अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विवादित था, उच्च न्यायालय ऐसे विवादित दस्तावेज़ के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है, विद्वान वकील ने चंद धवन बनाम जवाहर लाल (1992) 3 एससीसी 317 मालवा कॉटन एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बनाम विरसा सिंह सिद्धू (2008) 17 एससीसी 147 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था। इसलिए अपीलकर्ता कानूनी दायित्व से बचने के लिए अपने इस्तीफे की दलील नहीं दे सकती, वह भी तब जब इस्तीफा अपने आप में एक विवादित तथ्य है। जब तक मुकदमा नहीं चलता, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता अब निदेशक नहीं है और उत्तरदायी नहीं है। प्रतिवादी नंबर 2 और आरोपी कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन से संबंधित भौतिक समय में अपीलकर्ता एक निदेशक थी और एक निदेशक के रूप में कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखभाल कर रही थी और इसलिए उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि उसने कमीशन में अपराध करने में मिलीभगत की थी।

13. विद्वान वकील ने आगे कहा कि इसके अलावा शिकायत में दिए गए कथनों के अनुसार, अपीलकर्ता ने व्यापार वित्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता के पक्ष में 19 जनवरी 2005 को एक अपरिवर्तनीय गारंटी पत्र भी निष्पादित किया है। गारंटी के उक्त पत्र में,

अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से वचन दिया कि कंपनी द्वारा भुगतान न करने या उपेक्षा करने या अवैतनिक राशि का भुगतान करने से इनकार करने की स्थिति में उसे भुगतान करना होगा। वह आगे इस बात पर सहमत हुई कि गारंटी के तहत उसकी देनदारी और दायित्व तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उधारकर्ता सभी देनदारियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के बावजूद। गारंटी का बाध्यकारी खंड इस प्रकार पढ़ता है:

"मैं, गारंटर, स्पष्ट रूप से, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त सहमत हूं कि आपकी कंपनी हकदार होगी समझौते के तहत और उसके संबंध में आपकी कंपनी को ग्राहक द्वारा देय सभी राशियों के लिए ग्राहक से कोई मांग किए बिना या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही किए बिना इस गारंटी को लागू करना।"

विचाराधीन चेक अपीलकर्ता द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर जारी किए गए थे और इस्तीफे के साधारण आधार पर वह गारंटी पत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार पारस्परिक दायित्व से विचलित नहीं हो सकती है।

14. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने बनाया गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनु मेहता और अन्य (2014 की आपराधिक अपील संख्या 2228) में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में 17 अक्टूबर 2014 को निर्णय लिया गया और प्रस्तुत किया गया कि एक बार एनआई

अधिनियम की धारा 141 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 138 के तहत दायर एक शिकायत में मूल कथन यह है कि जिस समय अपराध किया गया था उस समय निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, मजिस्ट्रेट ऐसे निदेशक के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकता है और मूल कथन पर्याप्त है निदेशक के खिलाफ मामला बनाएं। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने में कोई अवैधता नहीं है।

15. हमने इस पर गहन विचार किया है दोनों पक्षों के वकील द्वारा विस्तार से दलीलें दी गईं। निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं (i) क्या चेक अनादरण के कथित अपराध के लिए अपीलकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 141 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है डिफॉल्ट कंपनी द्वारा ? (ii) क्या उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में सही था?

16. मामले की खूबियों पर गौर करने से पहले, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर की गई शिकायतों के प्रासंगिक हिस्सों पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार हैं:

"मैं कहता हूं कि आरोपी नंबर 1 की ओर से आरोपी नंबर 2 से 5 ने व्यापार वित्त के अनुरोध के साथ हमसे संपर्क किया है सुविधा और

तदनुसार उक्त सुविधा प्रदान की गई है हमारे द्वारा अभियुक्तों को उनके अनुरोध और आवश्यकता के अनुसार।

मैं कहता हूं कि आरोपी नंबर 1 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आरोपी नंबर 2, 3 और 5 निदेशक और आरोपी हैं नंबर 4 आरोपी का निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है नंबर 1 मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड - अग्रदाय। शिकायत से संबंधित और प्रासंगिक सभी भौतिक समय में आरोपी नंबर 2 से 5 आरोपी नंबर 1 के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार थे और आरोपी के दिन-प्रतिदिन के मामलों की भी देखभाल कर रहे हैं। नंबर 1 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी नंबर 2 से 5 आरोपी नंबर 1 के साथ उक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक/हस्ताक्षरकर्ता के रूप में वर्तमान अपराध के कमीशन में मुकदमा चलाने और/या शामिल होने के लिए उत्तरदायी हैं।

मैं कहता हूं कि पैरा 4 में बताया गया है कि आरोपी नंबर 2 से 5 हैं आरोपी नंबर 1 यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार होने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है में निहित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में अपनी ओर से विफलता की स्थिति में एक आपराधिक अपराध किया वैधानिक नोटिस दिनांक 03-11-08, जो उन्हें भेजा गया था दोनों आर.पी.ए.डी. के अंतर्गत; एवं यू.पी.सी. 06/11/08 को. मैं कहता हूं कि सभी आरोपियों को 08/11/08 को या इसके आसपास नोटिस प्राप्त हुआ था और यू.पी.सी. के माध्यम से भेजे गए नोटिस को तामील माना

जाता है, हालांकि आरोपी उपरोक्त अनादरित चेक के तहत हमारा भुगतान करने में विफल रहे और उपेक्षा की।"

17. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता, जो प्रबंध निदेशक की पत्नी थी, को कंपनी मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। लिमिटेड ने 1 जुलाई, 2004 को और 19 जनवरी, 2005 को एक गारंटी पत्र भी निष्पादित किया था। विचाराधीन चेक अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2008 के दौरान जारी किए गए थे। जहां तक चेक के अनादर का सवाल है, माना जाता है कि चेक पर अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता प्रबंध निदेशक नहीं था, बल्कि कंपनी का एक गैर-कार्यकारी निदेशक था। गैर-कार्यकारी निदेशक निस्संदेह कंपनी के प्रशासन का संरक्षक है, लेकिन वह कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में शामिल नहीं होता है। यह अपने व्यवसाय को चलाता है और केवल कार्यकारी गतिविधि की निगरानी करता है। किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रतिनियुक्त दायित्व को बांधने के लिए, भौतिक समय पर वह व्यक्ति कंपनी के मामलों के शीर्ष पर रहा होगा जो सक्रिय रूप से कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल करता है और विशेष रूप से जिम्मेदार है। इसके व्यवसाय का संचालन सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, उसे एन.आई अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति प्रावधान के दायरे में

नहीं आएगा। बार-बार, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि केवल वे व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के प्रभारी और संचालन के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। एक निदेशक, जो प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी नहीं था और जिम्मेदार नहीं था, एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा: "धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो परोक्ष दायित्व पैदा करता है और जिसे स्थापित कानून के अनुसार सख्ती से समझा जाना चाहिए। इसलिए एक शिकायत में बिना सोचे-समझे सरसरी बयान देना पर्याप्त नहीं है कि निदेशक (अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध) का प्रभारी और जिम्मेदार है निदेशक की भूमिका के बारे में और कुछ बताए बिना कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी को। लेकिन शिकायत में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे और किस तरीके से प्रतिवादी 1 इस आचरण के लिए आरोपी कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति जिम्मेदार था। इसके व्यवसाय का. यह दंडात्मक क़ानूनों की सख्त व्याख्या के अनुरूप है, विशेषकर, जहां ऐसा हो क़ानून परोक्ष दायित्व बनाते हैं।

एक कंपनी में कई निदेशक हो सकते हैं और बनाने पड़ सकते हैं किसी भी या सभी निदेशकों को एक शिकायत में केवल इस बयान के आधार पर आरोपी बनाना कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी

और जिम्मेदार हैं, इससे अधिक कुछ भी धारा 141 के तहत आवश्यकताओं की पर्याप्त या पर्याप्त पूर्ति नहीं है।

18. गिरधारी लाल गुप्ता बनाम डी.एच. मेहता एवं अन्य. (1971) 3 एससीसी 189, में इस न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति 'व्यवसाय के प्रभारी' का मतलब है कि उस व्यक्ति को कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय का समग्र नियंत्रण होना चाहिए।

19. किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह कंपनी का प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था या यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के साथ किया गया था। संबंधित निदेशक की सहमति या मिलीभगत, या समझौते पर किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार था [देखें: कर्नाटक राज्य बनाम प्रताप चंद और अन्य (1981) 2 एससीसी 335)।

20. दूसरे शब्दों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यही है किसी कंपनी के निदेशक को उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए। एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत कंपनी में निदेशक के खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए, जिसमें दिखाया जाए कि निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कैसे और किस तरह से जिम्मेदार था।

21. सबिता राममूर्ति और अन्य बनाम आर.बी.एस. चन्नबसवराध्या (2006) 10 एससीसी 581, द्वारा आयोजित किया गया थाइस न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है विशेष रूप से अनुभाग के शब्दों को पुनः प्रस्तुत करें, लेकिन जो आवश्यक है वह तथ्य का स्पष्ट विवरण है ताकि अदालत को प्रथम दृष्टया राय पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके कि अभियुक्त परोक्ष रूप से उत्तरदायी है धारा 141 एक कानूनी कल्पना पैदा करती है। उक्त प्रावधान के कारण, हालांकि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, लेकिन वह इसके लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होगा। जहां तक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत या निगमित कंपनी का संबंध है, इस तरह की परोक्ष देनदारी का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है, जब आवश्यक बयान, जो शिकायत याचिका में दिए जाने आवश्यक हैं, दिए गए हैं ताकि आरोपी को इसके लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। कंपनी द्वारा किया गया अपराध. किसी स्पष्ट कथन के बिना धारा के शब्दों को शब्दशः पुनः प्रस्तुत करना, उचित साक्ष्य द्वारा समर्थित तथ्य, ताकि आरोपी को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके, एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का आधार है।

22. जैसा कि पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एससीसी 343 में इस न्यायालय

द्वारा आयोजित किया गया था, किसी आपराधिक मामले में आरोपी को तलब करना गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को यूं ही क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को सम्मन देने के मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करनी होगी और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को समन करने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक होता है। मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए या अन्यथा उत्तर पाने के लिए शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से खुद भी सवाल पूछ सकते हैं और फिर जांच कर सकते हैं कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या किसी एक अभियुक्त द्वारा किया गया है।

23. गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में जिस पर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने बहुत अधिक भरोसा किया है, यह पैरा 33 (सी) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"किसी दिए गए मामले के तथ्यों में, समग्र रूप से पढ़ने पर शिकायत, उच्च न्यायालय मूल कथन की उपस्थिति के बावजूद, शिकायत में निदेशक की भूमिका के बारे में अधिक विवरण की अनुपस्थिति के

कारण शिकायत को रद्द कर सकता है। ऐसा कुछ बेदाग, निर्विवाद सबूतों के सामने आने के बाद हो सकता है जो संदिग्ध या संदेह या पूरी तरह से स्वीकार्य परिस्थितियों से परे हैं जो स्पष्ट रूप से संकेत दे सकते हैं कि निदेशक चेक जारी करने से चिंतित नहीं हो सकता है और उसे मुकदमे में खड़े होने के लिए कहना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। बुनियादी औसत योग्यता की उपस्थिति के बावजूद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निदेशक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। उदाहरण के लिए लाइलाज बीमारी से पीड़ित एक निदेशक का मामला लीजिए जो प्रासंगिक समय पर बिस्तर पर था या एक निदेशक जिसने चेक जारी करने से बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसे मामलों में, यदि उच्च न्यायालय आश्वस्त है कि ऐसे निदेशक पर मुकदमा चलाना केवल एक हाथ घुमाने की रणनीति है, तो उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है। यह कहना दोहराना आवश्यक है कि ऐसे मामले को स्थापित करने के लिए बेदाग , निर्विवाद साक्ष्य जो संदिग्ध या संदेह से परे हो या कुछ पूरी तरह से स्वीकार्य परिस्थितियों को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया जाए। ऐसे मामले इक्का-दुक्का हो सकते हैं लेकिन ऐसे मामले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता."

24. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, वर्तमान मामले की जांच की जाए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दो व्यक्तियों, अर्थात्, पराग तेजानी और हितेश हरिया को 14 सितंबर, 2019 से कंपनी

के निदेशक-संचालन के रूप में शामिल किया गया था। 17 दिसंबर, 2005 को कंपनी द्वारा उसी तारीख को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर। यह उसी तारीख को है जब अपीलकर्ता वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निदेशक नहीं रह गया था, जो कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विवादित नहीं है, शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने नव नियुक्त निदेशक-संचालन पराग तेजानी और हितेश को बनाया है। हरिया ने भी आरोपी के रूप में कहा कि सभी आरोपियों ने व्यापार वित्त सुविधा के अनुरोध के साथ उनसे संपर्क किया और उनके अनुरोध के अनुसार उक्त सुविधा प्रदान की गई। इस प्रकार यह आभास होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 को आरोपी कंपनी में निदेशकों के बदलाव के बारे में अच्छी तरह से पता है।

कंपनी में हुए विकास को जानने के बावजूद कि अपीलार्थी अब एक नहीं थाकंपनी में हुए घटनाक्रम को जानने के बावजूद कि अपीलकर्ता अब कंपनी का निदेशक नहीं है और दो नए निदेशकों को शामिल किया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 ने उन सभी को शिकायतों में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध करने का विकल्प चुना है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में इस तथ्य पर जोरदार ढंग से विवाद नहीं किया था। हमने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर उत्तर हलफनामे का अध्ययन किया है।

25. प्रतिवादी संख्या 2 के कथन का एक मात्र वाचन उच्च न्यायालय के समक्ष सुझाव दिया गया है कि उनके मामले से ऐसा प्रतीत

होता है कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में अपना इस्तीफा साबित नहीं किया है और यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने एक गंजा बयान देने और दस्तावेजों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए अपीलकर्ता पर बोझ डालने के अलावा, कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि सार्वजनिक दस्तावेज फॉर्म 32 और वार्षिक विवरणी जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं। दिलचस्प बात यह है कि, प्रतिवादी संख्या 2 एक ओर फॉर्म 32 की वास्तविकता के बारे में संदेह उठाता है, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसके माध्यम से डिफ़ॉल्ट कंपनी ने अपीलकर्ता के इस्तीफे और दो निदेशक-संचालन को शामिल करने के प्रभाव से निदेशकों के परिवर्तन की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को दी गई और दूसरी ओर, उन्होंने दो नवनियुक्त निदेशक-संचालन को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिनके नाम सूचित किए गए थे। उसी फॉर्म 32 द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार। प्रतिवादी/शिकायतकर्ता को एक ही समय में गर्म और ठंडा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब वह दस्तावेज़ की वास्तविकता से इंकार करता है, तो वह उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता और नव नियुक्त निदेशकों को आरोपी नहीं बना सकता।

26. हमने दाखिल वार्षिक विवरणी की प्रति का भी अवलोकन किया है मेसर्स एलीट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2006 के लिए, 31 मार्च, 2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अनुसार फॉर्म 20बी में प्रस्तुत किया गया। अनुसूची V के कॉलम IV...वार्षिक विवरणी के

भाग II के संबंध में जानकारी की आवश्यकता है निदेशक/प्रबंधक/सचिव (अतीत और वर्तमान) जिसमें देवीदासानी रविंदर पूजा-अपीलकर्ता के नाम के सामने यह उल्लेख किया गया था कि "समाप्ति की तिथि: 17-12-2005। माना जाता है कि, वार्षिक विवरणी की एक प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, इसलिए, हम उनका सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता द्वारा निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का तथ्य स्थापित हो गया है। निदेशकों को अभियुक्त के रूप में नियुक्त किया।

27. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया उचित परिप्रेक्ष्य में और यह कहकर रिट याचिकाओं को खारिज करने में गलती की कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर शिकायतों में अपीलकर्ता के खिलाफ विशिष्ट दावे किए गए थे। लेकिन इसके विपरीत, संपूर्ण शिकायत को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संपूर्ण शिकायत में, अपराध के घटित होने में अपीलकर्ता की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। यह स्थापित कानून है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत एक मामले को आकर्षित करने के लिए कंपनी के एक निदेशक द्वारा प्रत्यावर्तित दायित्व तय करने के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाई जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में, कथित अपराध के समय अपीलकर्ता न तो आरोपी कंपनी का निदेशक था और न ही कंपनी के दैनिक मामलों का प्रभारी या उसमें शामिल था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई फुसफुसाहट या साक्ष्य का एक टुकड़ा भी नहीं है कि अपीलकर्ता

द्वारा कोई कृत्य किया गया है जिससे उचित निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता को उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

28. पूरी शिकायत में न तो कंपनी के मामलों में अपीलकर्ता की भूमिका बताई गई और न ही यह बताया गया कि कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए अपीलकर्ता किस तरह जिम्मेदार है। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 13 अप्रैल, 2008 से 14 अक्टूबर, 2008 की अवधि के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा डिफॉल्ट कंपनी को व्यापार वित्त सुविधा प्रदान की गई थी, जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए थे, जो अनादरित हो गए। उससे काफी पहले 17 दिसंबर, 2005 को अपीलकर्ता ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के साथ पढ़ी गई धारा 138 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का शुद्ध दुरुपयोग है और इसे दहलीज पर रोकना होगा।

29. जहां तक गारंटी पत्र का सवाल है, यह एक नागरिक दायित्व के लिए रास्ता देता है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता हमेशा पहले उपाय के लिए आगे बढ़ा सकता है। उपयुक्त न्यायालय इसलिए यह तर्क कि चेक ऐसे गारंटी पत्र के आधार पर जारी किए गए थे और इसलिए अपीलकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 141 के साथ पढ़ी गई धारा 138

के तहत उत्तरदायी है, इन कार्यवाहियों में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. आपराधिक कानून को अमल में लाना कोई आसान बात नहीं है। उन पक्षों के बीच का हिसाब-किताब निपटाने के लिए जो एक नागरिक विवाद की प्रकृति के हैं, पार्टियों को आपराधिक कानून लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अदालतें इसके लिए केवल दर्शक नहीं बन सकती हैं। एनआई अधिनियम की धारा 138/141 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट से पहले, किसी व्यक्ति को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। यदि उच्च न्यायालयों को न्याय प्रशासन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत को रद्द कर देना चाहिए था जो कानून की प्रक्रिया के शुद्ध दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

31. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा यह मानना है यह शिकायत को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, और तदनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द करके इन अपीलों को अनुमति दें और ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करें।

कल्पना के. त्रिपाठी अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।